

श्री मोहन वाही

बनाम

आयुक्त, आय कर, वाराणसी अन्य

30 मार्च, 2001

[डॉ. ए. एस. आनंद, सी. जे., आर. सी. लाहोटी और डोराइस्वामी राजू, जे.जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

खंड 225 (3)-आयकर-ए.वाई. 1967-68 से 1969-70-निर्धारिती-फर्म के खिलाफ जारी कर वसूली प्रमाण पत्र-निर्धारिती से संबंधित घर की संपत्ति संलग्न और बिक्री के लिए घोषणा जारी-नीलामी-खरीदार की बोली स्वीकार की गई-अपील में, निर्धारिती-फर्म के खिलाफ आय-जोड़ की मांग समाप्त हो गई और शून्य हो गई-लेकिन कर वसूली अधिकारी ने बिक्री को सीमित कर दिया और नीलामी-खरीदार के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया-मान्यता:यदि कर की मांग को घटाकर शून्य कर दिया जाता है, तो कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि नहीं करने के लिए बाध्य है- आर. 56 न तो एक अनावश्यक है और न ही एक औपचारिक प्रावधान है- यह कर वसूली अधिकारी पर बिक्री की सचेत रूप से पुष्टि करने का दायित्व डालता है-यदि कोई बाद की घटना मामले की जड़ तक जाती है, तो कर वसूली अधिकारी को बिक्री की पुष्टि करने से इनकार करना चाहिए- इसलिए, नीलामी बिक्री को अलग कर दिया गया है- आयकर नियम- दूसरी अनुसूची, नियम 56

दूसरी अनुसूची में नियम 56- ए.वाई. 1967-68 से 1969-70-निर्धारिती-फर्म के खिलाफ जारी डिमांड-सर्विस ऑफ-टक्स रिकवरी सर्टिफिकेट का नोटिस-निर्धारिती से संबंधित घर की संपत्ति कुर्क और बिक्री के लिए घोषणा जारी-नीलामी-खरीदार की बोली स्वीकार की गई-अपील में, निर्धारिती-फर्म के खिलाफ आयकर की मांग समाप्त हो गई

और शून्य हो गई-यह भी माना गया कि निर्धारिती को मांग नोटिस नहीं दिया गया था-लेकिन कर वसूली अधिकारी ने बिक्री की पुष्टि की और नीलामी-खरीदार के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया। निर्धारिती पर मांग की सूचना की सेवा अनिवार्य है-मांग की सूचना की गैर-सेवा वसूली कार्यवाही की जड़ तक जाती है-मांग की सूचना की सेवा के बिना संपत्ति की बिक्री अमान्य है और रद्द होने के लिए उत्तरदायी है।

शब्द और वाक्यांश -

"कम"-का अर्थ। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 225 (3) के संदर्भ में किया गया।

अपीलकर्ता और उसके भाई ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और साझेदारी फर्म के आयकर आकलन को मूल्यांकन वर्षों 1967-68 से 1969-70 के लिए अंतिम रूप दिया गया। वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जिसके अनुसार अपीलकर्ता और उसके भाई की घर की संपत्ति कुर्क की गई थी और संपत्ति की बिक्री के लिए एक घोषणा जारी की गई थी। प्रत्यर्थी सं. 3 की छिपाई स्वीकार कर ली गई। हालांकि, अपील में, निर्धारिती-फर्म के खिलाफ आने वाले कर की कई मांगें समाप्त हो गईं और इसलिए, शून्य हो गईं। अपील में यह भी कहा गया था कि निर्धारिती-फर्म को मांग नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन कर वसूली अधिकारी ने बिक्री की पुष्टि की और प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठा:

(i) क्या कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि कर सकता था। जब किस कर की वसूली के लिए कर के कारण मांग की जाती है क्या प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया था?

(ii) खंड 156 के तहत मांग की सूचना का क्या प्रभाव पड़ता है आय कर अधिनियम, 1961 बिक्री पर कर निर्धारण पर लागू नहीं किया गया है। आय कर अवशिष्ट की वसूली के लिए आयोजित?

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 225 (3) में आने वाले "कम" शब्द में एक ऐसा मामला भी शामिल होगा जिसमें किसी अपील या आयकर अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही पर मांग को घटाकर शून्य कर दिया गया हो। कर वसूली अधिकारी मांग में इस तरह की कमी को लागू करने और तदनुसार प्रमाण पत्र में संशोधन या रद्द करने के लिए बाध्य है। दूसरी अनुसूची के भाग III की योजना इंगित करती है कि बिक्री की कार्यवाही उनके आत्यन्तिक होने पर समाप्त हो जाती है, जहां आखिरकार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना बाकी है। हालांकि, कर वसूली अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश अनिवार्य है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की प्रभावशीलता को अनुसूची में नियम 56 को शामिल करके कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के आदेश पर निर्भर किया गया है। यह सच है कि आम तौर पर यदि आयकर नियमों के नियम 60, 61 या 62 के तहत बिक्री को अलग करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है और बिक्री की तारीख से 30 दिन समाप्त हो गए हैं, तो कर वसूली अधिकारी को बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देना होगा। फिर भी, वास्तव में एक आदेश दिया जाना चाहिए। अधिनियम की खंड 225 (3) और दूसरी अनुसूची के नियम 56 और 63 का संयुक्त प्रभाव यह है कि यदि बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश को वास्तव में कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किए जाने से पहले, अपील या अधिनियम के तहत अन्य कार्यवाही में किए गए आदेश के परिणामस्वरूप कर की मांग को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तो कर वसूली अधिकारी प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए बाध्य है और जैसे ही प्रमाण पत्र रद्द

किया जाता है, उसे बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं होगी। बिक्री, कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होने के कारण, पुष्टि के अभाव में जमीन पर गिर जाएगी।[919-ई-एच]

2. निर्धारिती के खिलाफ मांग निश्चित रूप से घटकर शून्य रह गई। यह तथ्य आयकर अधिकारी के साथ-साथ आयकर आयुक्त के संज्ञान में था। विभाग की जानकारी में तथ्यों को देखते हुए, कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि नहीं कर सकते थे। आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में नियम 56 न तो अनावश्यक है और न ही कठोर प्रावधान है। यह कर वसूली अधिकारी पर एक दायित्व डालता है कि वह सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिक्री की पुष्टि करने का आदेश पारित करे, जिसकी पुष्टि की जानी है। नियम 63 के तहत, बिक्री की पुष्टि स्वचालित नहीं है। बिक्री को आत्यन्तिक बनाने के लिए बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश पर विचार किया जाता है। आम तौर पर, नियम 60, 61 या 62 के तहत किसी आवेदन की अनुपस्थिति में, बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर, कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करेगा। हालांकि, बिक्री की तारीख और बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश के वास्तविक पारित होने के बीच यदि कोई घटना होती है या कोई तथ्य कर वसूली अधिकारी के ध्यान में आता है जो मामले की जड़ तक जाता है, तो कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करने से इनकार कर सकता है, यह तथ्य कि बिक्री एक अनुमानित मांग के लिए आयोजित की जा रही थी जो कि काल्पनिक पाई गई है या वास्तव में या कानून की नजर में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, एक ऐसी घटना है जो कर वसूली अधिकारी को बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित नहीं करने के लिए बाध्य करेगी और बल्कि उसे रद्द कर देगी।[920-डी-एच]

जनक राज बनाम गुरदियाल सिंह, [1967] 2 एससीआर 77; सरदार गोविंदराव

महादिक बनाम देवी सहाय, आकाशवाणी (1982) एससी 989 और पदनाथिल रुग्मिनी अम्मा बनाम पीके। अब्दुल्ला, जे. टी. (1996) 1 एस. सी. 381, संदर्भित।

3. दूसरी अनुसूची के तहत वसूली के लिए कदम उठाने से पहले अधिनियम की खंड 156 के तहत निर्धारिती पर मांग की सूचना की सेवा अनिवार्य है। मांग के नोटिस की गैर-सेवा वसूली के लिए बाद की कार्यवाही की वैधता की जड़ तक जाती है। मांग की सूचना दिए बिना शुरू की गई वसूली कार्यवाही में आयोजित बिक्री अमान्य होगी और इसलिए प्रश्न में बुलाए जाने पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी। [925-बी]

आयकर अधिकारी, कोलार सर्कल बनाम सेघु बुचिया सर्ती, (1964) 52 1 टीआर 538; होमली इंडस्ट्रीज बनाम बिक्री कर अधिकारी, (1976) 37 एसटीसी 483; भारत संघ बनाम जार्डिन हैंडरसन लिमिटेड, (1579) 118 आईटीआर 112 और सुरिंदर नाथ कपूर बनाम भारत संघ, एआईआर (1988) एससी 1777, का उल्लेख किया गया है।

राम स्वरूप गुप्ता बनाम बिहारी लाल बलदेव प्रसाद, (1974) 95 आईटीआर 339 (सभी); सुनील कुमार सिंह देव बनाम कर वसूली अधिकारी, (1987) 166 आईटीआर 882 (ओरी); घनश्यामलाल बनाम एम. पी. राज्य, (1961) एम. पी. एल. जे. एस. एन. 218 (एम. पी.); मनमोहन लाल शुक्ला बनाम राजस्व बोर्ड, एम. पी., (1964) एम. पी. एल. जे. 32 (एम. पी.) और प्रेमचंद रामचंद बनाम राजस्व बोर्ड, (1964) एम. पी. एल. जे. 337 (एम. पी.) को मंजूरी दी गई।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल याचिका सं 2488/2001

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सी.एम.डब्ल्यू.पी सं. 640/1999 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 11.1.2000 से।

एम. एल. वर्मा, एन. एन. गोस्वामी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, रणबीर चंद्र, सुश्री.सुरुचि अग्रवाल, राजीव त्यागी, बी. वी. बलराम दास, सुश्री सुषमा सूरी, सुशील

उपस्थित दलों के लिए कुमार जैन, राजेश कुमार और सुश्री नीरा गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, जे. द्वारा पारित किया गया था :-

प्रासंगिक तथ्य अस्पष्ट हैं और किसी भी विवाद के दायरे से परे हैं। स्वर्गीय भगवती प्रसाद के पास एक घर की संपत्ति थी जिसे डी-53/91-डी, लक्सा, वाराणसी (इसके बाद घर की संपत्ति के रूप में संदर्भित) के रूप में वर्णित किया गया था। उनके चार बेटे थे-पी, एस, आर और के। वर्ष 1962 की उनकी वसीयत के तहत, वर्ष 1965 में जांच की गई, घर की संपत्ति उनके चार बेटों को हस्तांतरित कर दी गई। बड़े दो बेटों-पी और 8 ने एक साझेदारी में प्रवेश किया था जिसे मैसर्स यूनाइटेड प्रोविंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, लक्सा, वाराणसी (संक्षेप में यूपीसीसी) के रूप में जाना जाता है जो भारी मशीनरी और रोड रोलर्स के आयात और बिक्री में काम करता है। श्रम समस्याओं के परिणामस्वरूप वर्ष 1967 में फर्म का व्यवसाय ध्वस्त हो गया। साझेदारों ने वाराणसी छोड़ दिया और कहीं और चले गए। वर्ष 1972 में, यू. पी. सी. सी. फर्म के आय-कर आकलन को मूल्यांकन वर्षों 1967-1968 से 1969-1970 के लिए वित्तपोषित किया गया था। वसूली प्रमाणपत्र 1973-1974 में जारी किए गए थे, जिसके अनुसार घर की संपत्ति कुर्क की गई थी। 3.12.1979 पर संपत्ति की बिक्री के लिए एक घोषणा जारी की गई थी जिसमें रु. 30,82,000 की मांग और रु. 1,70,000 पर अपसेट मूल्य निर्धारित किया गया था। 11.1.1980 पर, सार्वजनिक नीलामी में, प्रत्यर्थी नं. 3 ने संपत्ति को रुपये 1,70,000 (जो कि परेशान करने वाली कीमत थी) में खरीदने का प्रस्ताव रखा। बिक्री का संचालन करने वाले अधिकारी ने बोली स्वीकार कर ली। 42,500 की राशि जो नीलामी की राशि का एक चौथाई हिस्सा है, नीलामी-खरीदार द्वारा बोली की स्वीकृति के साथ-साथ 11.1.1980 पर जमा किया गया था। 1,27,500 रुपये की शेष राशि को 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर 25.1.1980 पर जमा किया गया था।

आर, तीसरे भाई की मृत्यु हो गई थी। उनकी विधवा, पद्मा ने दीवानी न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि चार भाइयों की अविभाजित संपत्ति और किसी भी मामले में भाइयों के हिस्से, जो फर्म में भागीदार नहीं थे, को कुर्क नहीं किया जा सकता था और फर्म के खिलाफ बकाया की वसूली के लिए बिक्री के लिए विज्ञापन नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने बिक्री पर एक विज्ञापन अंतरिम प्रतिबंध की भी मांग की। 9.1.1980 पर, सिविल जज की अदालत ने नीलामी बिक्री पर रोक लगाना उचित नहीं समझा, लेकिन फिर भी महसूस किया कि नीलामी बिक्री की पुष्टि पर रोक लगाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। तदनुसार, भारत संघ और आयकर विभाग के अधिकारियों को एक अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा से बिक्री की पुष्टि नहीं करने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 1984 में नीलामी-खरीदार, प्रत्यर्थी सं 3 यहाँ, मुकदमा में एक पक्ष के रूप में भी शामिल किया गया था। अंतरिम निषेधाज्ञा तब तक जारी रही जब तक कि 12.1.1998 पर उपस्थित होने की चूक में मुकदमा खुद खारिज नहीं हो गया। 13.1.1998 पर मुकदमे की बहाली के मुकदमा एक आवेदन दायर किया गया था। 30.7.1999 पर मुकदमा फाइल में बहाल कर दिया गया था।

यू. पी. सी. सी. फर्म के खिलाफ किए गए आकलन सभी एक तरफा थे और फर्म के खिलाफ की गई मांग के एक बड़े हिस्से में जुर्माना और ब्याज शामिल थे। फर्म ने आयकर विभाग के पदानुक्रम में इस मामले को उठाया। निर्धारण के आदेशों को चुनौती आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विफल रही, जिन्होंने निर्धारण वर्ष 1967-1968 से 1970-1971 से संबंधित अपीलों को खारिज कर दिया क्योंकि वे सीमा की निर्धारित अवधि से परे दायर की गई थीं। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के समक्ष चार अपीलें दायर की गईं। 11.12.1987 दिनांकित एक आदेश द्वारा सभी चार अपीलों की अनुमति दी गई थी। न्यायाधिकरण ने एक राय बनाई कि पर्याप्त

कारण था जिसने निर्धारिती को समय पर सी. आई. टी. (ए) के समक्ष अपील दायर करने से रोक दिया था और इसलिए अपीलों को गुण-दोष के आधार पर सी. आई. टी. (ए) की फाइल पर बहाल किया जाना चाहिए, तदनुसार आदेश दिया गया। अपने आदेश के दौरान न्यायाधिकरण ने सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को बरकरार रखा कि "यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारिती को मांग नोटिस दिया गया था।" इस तरह से रिमांड पर लिए जाने पर, सी. आई. टी. (ए) द्वारा योग्यता के आधार पर अपीलों पर सुनवाई की गई। कर, जुर्माना और ब्याज के कारण मांग से संबंधित अधिकांश मामलों को सी. आई. टी. (अपील) के स्तर पर हल किया गया था, जबकि 1967-1968 के लिए संदर्भित कर मांग को न्यायाधिकरण के समक्ष हल किया गया था। तथ्य यह है कि वर्ष 1989 में अलग-अलग तिथियों पर निर्धारिती फर्म के खिलाफ कई मांगों का सफाया कर दिया गया था और इसलिए वे घटकर शून्य रह गई थीं। आयकर अधिकारी, वार्ड II, वाराणसी ने आयकर आयुक्त, इलाहाबाद को लिखा कि निर्धारिती फर्म के खिलाफ उठाई गई विभिन्न मांगों को घटाकर शून्य कर दिया गया है। निर्धारिती फर्म पर, मेसर्स यूपीसीसी ने आयकर अधिकारी, वार्ड II, वाराणसी को लिखा कि कर और जुर्माने की सभी मांगों को रद्द/समाप्त कर दिया गया है, धनवापसी देय है और कर वसूली अधिकारी को सभी वसूली प्रमाणपत्रों को रद्द करने की सलाह दी जा सकती है। आवेदन की प्रति कर वसूली अधिकारी को दी गई थी। आई. डी. 1 पर निर्धारिती फर्म के अधिवक्ता ने आई. टी. ओ., वार्ड-2, वाराणसी को लिखा कि फर्म के खिलाफ सभी मांगों के अस्तित्व को समाप्त करने और इसके बजाय फर्म को धनवापसी के कारण, यह पुष्टि की जा सकती है कि फर्म के खिलाफ मांगों के लिए जारी किए गए सभी वसूली प्रमाण पत्र वापस ले लिए गए थे/रद्द कर दिए गए थे। आई. टी. ओ., वार्ड II, वाराणसी से आयकर आयुक्त को आई. डी. 1 दिनांकित पत्र की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई थी।

उपरोक्त संचारों के बावजूद, प्रतिवादी 3 के पक्ष में 25.3.1998 की बिक्री पर पुष्टि कर वसूली अधिकारी द्वारा की गई थी, हालांकि केवल घर की संपत्ति में पी और एस के ब्याज के संबंध में और प्रतिवादी संख्या 3 को एक बिक्री प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। बिक्री की पुष्टि करने वाले कर वसूली अधिकारी के आदेश को सी. आई. टी., वाराणसी के समक्ष यू. पी. सी. सी. और उसके भागीदार पी. और एस. द्वारा अधिनियम की खंड 264 के तहत याचिका दायर करके जारी किया गया था। सी. आई. टी. ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से याचिका को यह राय देते हुए खारिज कर दिया कि 1 पर आयोजित नीलामी बिक्री के बाद जो कुछ भी हुआ वह महत्वहीन था और कर वसूली अधिकारी के पास बिक्री की पुष्टि करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। एस, याचिकाकर्ता ने तब हमारे समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की, जिसमें बिक्री की पुष्टि करने वाले कर वसूली अधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई और प्रतिवादी संख्या 3 को सी. एल. टी. दिनांकित 21.5.1999 के आदेश के लिए भी बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह तथ्य कि फर्म (और भागीदारों) के खिलाफ सभी मांगों का अस्तित्व 1996 और 1997 तक समाप्त हो गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका के पैरा 5 में सकारात्मक रूप से दावा किया गया है और आयकर आयुक्त की ओर से दायर जवाबी-हलफनामे में इनकार नहीं किया गया है। इसी तरह यह तथ्य भी कि फर्म यूपीसीसी के खिलाफ मांगों को रद्द कर दिया गया था और इस तथ्य को आईटीओ, वार्ड II, वाराणसी द्वारा आयकर आयुक्त, इलाहाबाद को उनके दिनांकित 26.3.1990 पत्र द्वारा से सूचित किया गया था, जवाबी-हलफनामे में भी स्वीकार किया गया है। हालांकि, इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीडित याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अवकाश के लिए यह याचिका दायर की है।

अवकाश अनुदत्त गई।

इस अपील में निर्णय के लिए दो प्रश्न उठते हैं:

(i) क्या कर वसूली अधिकारी 25.3.1998 पर बिक्री की पुष्टि कर सकता था जब कर की वसूली के लिए कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे; और

(ii) खंड 156 के तहत मांग की सूचना का क्या प्रभाव पड़ता है आय-कर अधिनियम, 1961 आय-कर अवशिष्ट की वसूली के लिए आयोजित बिक्री पर निर्धारिती पर लागू नहीं किया गया है?

पहले प्रश्न को लेते हुए, खंड 222 के अनुसार जहां कोई निर्धारिती चूक करता है या कर अवशिष्ट करने में चूक करता है, कर वसूली अधिकारी निर्धारिती से बकाया राशि निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और ऐसे निर्धारिती से एक या अधिक तरीकों से निर्दिष्ट राशि की वसूली करने के लिए आगे बढ़ेगा जिसमें निर्धारिती की अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री शामिल है। दूसरी अनुसूची में कर की वसूली की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हम दूसरी अनुसूची में निहित और अपने उद्देश्य के लिए प्रासंगिक कुछ नियमों का उल्लेख करेंगे। अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री से संबंधित नियम दूसरी अनुसूची के भाग III में निहित हैं। नियम 56 में प्रावधान है कि बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दी जाएगी और यह कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। नियम 56 का पालन करने वाले नियमों में निहित कई प्रावधान सिविल अदालतों द्वारा पारित फरमानों को हटाने से संबंधित सी. पी. सी. के आदेश 21 में निहित अचल संपत्ति बिक्री से संबंधित प्रावधानों के समान हैं। हालाँकि, सी. पी. सी. के आदेश 21 में, दूसरी अनुसूची के नियम 56 के समान कोई प्रावधान नहीं पाया गया है। नियम 60 में बिक्री की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट राशि जमा करने पर चूककर्ता या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा रही अचल संपत्ति की बिक्री को अलग करने के लिए एक आवेदन का प्रावधान है। नियम

61 अनुसूची के तहत चूककर्ता पर नोटिस न देने के आधार पर या बिक्री के प्रकाशन या संचालन में भौतिक अनियमितता के आधार पर अचल संपत्ति की बिक्री को अलग करने के आवेदन से संबंधित है। नियम 62 के तहत खरीददार के आवेदन पर इस आधार पर बिक्री को अलग रखा जा सकता है कि चूककर्ता का बेची गई संपत्ति में कोई बिक्री योग्य ब्याज नहीं था। निर्धारित समय सीमा जिसके भीतर नियम 60, 61 या 62 के तहत आवेदन किया जा सकता है, बिक्री की तारीख से 30 दिन है। जहां बिक्री को अलग करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है या ऐसा आवेदन करने की अनुमति नहीं है, कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देगा और उसके बाद बिक्री आत्यन्तिक हो जाएगी। किसी बिक्री या अचल संपत्ति के आत्यन्तिक होने पर, नियम 65 के तहत एक बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

खंड 224 के तहत, एक निर्धारित कर वसूली अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी भी प्रमाण पत्र की शुद्धता पर विवाद नहीं कर सकता है, लेकिन कर वसूली अधिकारी के लिए किसी भी कारण से प्रमाण पत्र को रद्द करना वैध है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है या उसमें किसी लिपिक या किसी कृत्रिम त्रुटि को सुधारना आवश्यक समझता है। खंड 225 की उप-खंड (3) निम्नानुसार प्रदान करती है:-

225. प्रमाणपत्र के अनुसरण में कार्यवाही पर रोक और उसका संशोधन या रद्द करना।

XXX XXX XXX

(3), जहां एक प्रमाण पत्र तैयार किया गया है और इस अधिनियम के तहत एक अपील या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप बकाया मांग की राशि को घटाया गया है, कर वसूली अधिकारी, जब आदेश जो ऐसी अपील या अन्य कार्यवाही का विषय था, अंतिम और निर्णायक हो गया है, तो प्रमाण पत्र में संशोधन करेगा, या इसे रद्द कर

देगा, जैसा भी मामला हो।

खंड 225 की उप-खंड (3) में 'घटाया' शब्द में एक ऐसा मामला शामिल होगा जिसमें आयकर अधिनियम के तहत किसी अपील या किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप की गई मांग को भी घटाकर शून्य कर दिया गया है। कर वसूली अधिकारी मांग में इस तरह की कमी को लागू करने और तदनुसार प्रमाण पत्र में संशोधन या रद्द करने के लिए बाध्य है। दूसरी अनुसूची के भाग III की योजना इंगित करती है कि बिक्री की कार्यवाही उनके आत्यन्तिक होने पर समाप्त हो जाती है, जहां आखिरकार बिक्री प्रमाण पत्र जारी करना बाकी है। हालांकि, कर वसूली अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश अनिवार्य है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पक्ष में सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की प्रभावशीलता अनुसूची में नियम 56 को शामिल करके कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के आदेश पर निर्भर करने के लिए बनाई गई है। यह सच है कि आम तौर पर यदि नियम 60, 61 या 62 के तहत बिक्री को अलग रखने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है और बिक्री की तारीख से 30 दिन समाप्त हो गए हैं, तो कर वसूली अधिकारी को बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देना होगा। फिर भी, वास्तव में एक आदेश दिया जाना चाहिए। अधिनियम की खंड 225 की उप-खंड (3) और दूसरी अनुसूची के नियम 56 और नियम 63 का संयुक्त प्रभाव यह है कि यदि बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश को वास्तव में कर वसूली अधिकारी द्वारा पारित किए जाने से पहले, अपील या अधिनियम के तहत अन्य कार्यवाही में किए गए आदेश के परिणामस्वरूप कर की मांग को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तो कर वसूली अधिकारी प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए बाध्य है और जैसे ही प्रमाण पत्र रद्द किया जाता है, उसे बिक्री की पुष्टि करने का आदेश देने की कोई शक्ति नहीं होगी। बिक्री स्वयं कर वसूली अधिकारी द्वारा पुष्टि के अधीन होने के कारण, पुष्टि के अभाव में जमीन पर गिर जाएगी।

हाथ में मामले में बिक्री 11.1.1980 पर आयोजित की गई थी। निर्धारिती या नीलामी खरीदार या संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा बिक्री को अलग करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित कर सकता था। हालांकि, कर वसूली अधिकारी को दीवानी अदालत के रिट द्वारा बिक्री की पुष्टि करने से रोक दिया गया था। दीवानी अदालत द्वारा जारी अंतरिम आदेश ने 12.1.1998 पर काम करना बंद कर दिया, जहां कर वसूली अधिकारी द्वारा 25.3.1998 पर पुष्टि का आदेश पारित किए जाने के बाद बीच में हुई महत्वपूर्ण घटना को नजरअंदाज कर दिया गया था। 25.3.1998 से पहले, निर्धारिती के खिलाफ मांग निश्चित रूप से घटकर शून्य रह गई थी। यह तथ्य आयकर अधिकारी के साथ-साथ आयकर आयुक्त के संज्ञान में था। फर्म मेसर्स यूपीसीसी ने अपने दिनांक 22.11.1996 (अनुलग्नक पी-) द्वारा से आयकर अधिकारी के साथ-साथ कर वसूली अधिकारी का भी ध्यान आकर्षित किया था।

6). आई. डी. 1 पर, निर्धारिती के वकील ने विशेष रूप से आयकर अधिकारी से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा था कि क्या निर्धारिती फर्म के खिलाफ जारी किए गए सभी वसूली प्रमाण पत्र वापस ले लिए गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। विभाग की जानकारी में तथ्यों और इस तरह किए गए संचार को देखते हुए, कर वसूली अधिकारी 25.3.1998 पर बिक्री की पुष्टि नहीं कर सकते थे। आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में नियम 56 न तो अनावश्यक है और न ही औपचारिक प्रावधान है। यह कर वसूली अधिकारी पर एक दायित्व डालता है कि वह सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री से संबंधित प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बिक्री की पुष्टि करने का आदेश पारित करे, जिसकी पुष्टि की जानी है। नियम 63 के तहत, बिक्री की पुष्टि स्वचालित नहीं है। बिक्री को आत्यन्तिक बनाने के लिए बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश पर विचार किया जाता है। आम तौर पर, नियम 60, 61 या 62 के तहत आवेदन किए जाने

या किए जाने पर खारिज किए जाने की अनुपस्थिति में मैं, बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करेगा। हालाँकि, बिक्री की तारीख और बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश के वास्तविक पारित होने के बीच यदि कोई घटना होती है या कोई तथ्य कर वसूली अधिकारी के ध्यान में आता है जो मामले की जड़ तक जाता है, तो कर वसूली अधिकारी बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करने से इनकार कर सकता है। तथ्य यह है कि बिक्री एक अनुमानित मांग के लिए आयोजित की जा रही थी जो कि काल्पनिक पाई गई है या जो वास्तव में या कानून की नजर में मौजूद नहीं है, एक ऐसी घटना है जो कर वसूली अधिकारी को बिक्री की पुष्टि करने वाला आदेश पारित नहीं करने और उसे रद्द करने के लिए बाध्य करेगी। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बिक्री को दरकिनार करके याचिकाकर्ता-अपीलार्थी को राहत नहीं देने में गलती की।

श्री एस. के. जैन, नीलामी-खरीदार के पक्ष में पक्षपाती वकील, प्रत्यर्थी संख्या 3, ने जनक राज बनाम गुरदियाल सिंह और अन्न, (1967) 2 एस. सी. आर. 77 और सरदार गोविंदराव महादिक और अंज बनाम का उल्लेख किया। देवी सहाय और अन्य, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 989 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार डिक्री के निष्पादन में बिक्री हो जाने के बाद, बिक्री की पुष्टि इस तथ्य के बावजूद की जानी चाहिए कि बिक्री के आयोजन के बाद, डिक्री को अलग कर दिया गया था। जनक राज के मामले में, एक एकतरफा आदेश के निष्पादन में बिक्री आयोजित की गई थी। एकतरफा डिक्री को बिक्री की तारीख के बाद, लेकिन बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश के पारित होने से पहले अलग कर दिया गया था। इस कौव ने कहा कि सी. पी. सी. के आदेश 21 के नियम 8 प्रतिशत से 91 के तहत उपलब्ध आधारों पर बिक्री को अलग करने के लिए एक आवेदन की अनुपस्थिति में मैं, अदालत बिक्री की पुष्टि करने से इनकार नहीं कर सकती थी। हालाँकि, इस मामले में ही, इस अदालत ने (पृष्ठ 80 पर)

कहा है कि ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें नियम 89 से 91 के प्रावधानों के अलावा अदालत बिक्री की पुष्टि करने से इनकार कर सकती है, उदाहरण के लिए, जहां निर्णय देनदार को नोटिस दिए बिना बिक्री आयोजित की जाती है, या जहां अदालत को आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में गुमराह किया जाता है या जहां उस समय कोई डिक्री मौजूद नहीं थी जब बिक्री आयोजित की गई थी। सदर गोविंदराव महादिक के मामले में जनक राज का मामला भेजा गया था। अदालत ने एक डिक्री धारक के पक्ष में आयोजित अदालती नीलामी और जहां नीलामी खरीदार एक बाहरी व्यक्ति या एक अजनबी है, के बीच अंतर किया है। बिक्री की पुष्टि होने से पहले डिक्री का अस्तित्व समाप्त होने के मामले में, बिक्री की पुष्टि करने से इनकार किया जा सकता है, लेकिन बाद के मामले में, अजनबी के पक्ष में इक्विटी की रक्षा की जानी चाहिए और निर्णय देनदार को उस डिक्री के निष्पादन पर रोक प्राप्त नहीं करने के लिए अपनी ओर से चूक के लिए पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए जहां से इसे चुनौती दी गई थी। हालांकि नीलामी खरीदार के लिए नियुक्त वकील ने इन निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, लेकिन यह देखने के लिए पर्याप्त है कि ये सी. पी. सी. के आदेश 21 के तहत आयोजित नीलामी बिक्री के मामले हैं और इसलिए, इसमें निहित नियम 56 को देखते हुए आयकर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के तहत आयोजित नीलामी बिक्री के मामले में लागू नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, इन निर्णयों में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों पर विचार किया है जहां नीलामी बिक्री आयोजित होने के बावजूद और बिक्री को अलग रखने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया है, फिर भी असाधारण स्थितियों में बिक्री की पुष्टि करने से इनकार किया जा सकता है और इसे अलग किया जा सकता है। श्री एस. के. जुइन ने पदनाथिल रुग्मिनी अम्मा बनाम पी. के. पर भी भरोसा किया। अब्दुल्ला, जे. टी. (1996) 1 एस. सी. 381, जिसमें इस अदालत ने कहा है कि जब तक नीलामी खरीदारों को संरक्षित नहीं किया जाता है, तब तक अदालत की

नीलामी में बेची जाने वाली संपत्तियों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा। यह सच है कि सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति की बिक्री की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अनुमानित अवशिष्ट की वसूली के लिए कार्यवाही का सामना करने वाले नागरिक को बिक्री की पुष्टि होने से पहले न्यायिक या अर्ध-न्यायिक घोषणा के बावजूद अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, कि कोई अवशिष्ट नहीं था। यह अवलोकन सभी आयकर अधिनियम की योजना के तहत लागू होता है, प्रासंगिक प्रावधान जिनके बारे में हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

अब हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। अधिनियम की खंड 156 निम्नानुसार प्रदान करती है:-

“56. मांग की सूचना। जब इस अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, जुर्माना, जुर्माना या कोई अन्य राशि देय होती है, तो निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को इस तरह से देय राशि को निर्दिष्ट करते हुए निर्धारित प्रपत्र में मांग की सूचना देगा।”

यदि खंड 156 के तहत मांग की सूचना में निर्दिष्ट राशि है उप-खंड (1) द्वारा सीमित समय के भीतर या खंड 220 की उप-खंड (3) के तहत विस्तारित भुगतान नहीं किया गया है, तो निर्धारिती को खंड 220 की उप-खंड (4) के तहत चूक माना जाएगा। कर वसूली प्रमाणपत्र खंड 222 के तहत तब जारी किया जा सकता है जब कोई निर्धारिती चूक करता है या उसे चूक में माना जाता है। दूसरी अनुसूची के तहत कर की वसूली के लिए एक चूककर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस प्रकार खंड 156 निर्धारण अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम का प्रावधान करती है जिसके बिना निर्धारिती को चूककर्ता नहीं कहा जा सकता है, खंड 156 में

'होगा' शब्द के उपयोग का तात्पर्य है कि वसूली कार्यवाही शुरू करने से पहले मांग सूचना की सेवा अनिवार्य है और यह बाद की वसूली कार्यवाही का आधार है।

हम पहले ही बता चुके हैं। सी.आई.टी. (अपील) और न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष यह था कि मांग की सूचना या निर्धारिती को नहीं दी गई थी। इसलिए, वसूली की कार्यवाही शुरू करने का आधार मौजूद नहीं था और न तो निर्धारिती को चूक में माना जा सकता था और न ही उसके खिलाफ कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू की जा सकती थी।

आयकर अधिनियम, 1922 की खंड 29 में निहित आयकर अधिनियम, 1961 की खंड 156 के अनुरूप प्रावधान आयकर अधिकारी, कोलार सर्कल और एनी में इस न्यायालय के विचार के लिए आया:बनाम सेधु बुचिया सेट्टी, (1964) 52 आईटीआर 538। हिदायतुल्ला, जे. (उस समय उनके अधिपति के रूप में) का मानना था कि मांग किए जाने के बाद, कर जुर्माना और ब्याज सरकार के कारण ऋण बन जाता है 'मांग की सूचना कई मायनों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है'। इसकी अवज्ञा करने से निर्धारिती चूककर्ता बन जाता है। यह भूमि राजस्व के बकाया के रूप में कर के उपचार के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। उनके प्रभुपाद ने इस बात पर जोर दिया कि मांग की सूचना की सेवा के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। (i) जब मांग की सूचना का पालन नहीं किया जाता है, तो निर्धारिती को चूक करने वाले व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है; (ii) मांग की सूचना जारी होने के बाद भुगतान करने में निर्धारिती की विफलता पर, वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और कर की राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में माना जा सकता है। तथापि, इस मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि आयकर अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण को अधिनियम के तहत किसी आदेश के कारण बदला जाता है-घटाया या बढ़ाया जाता है, तो यह आयकर अधिकारी का कर्तव्य है कि वह निर्धारित प्रपत्र में मांग की नई सूचना

जारी करे और कर निर्धारण पर कार्य करे। जे. हिदायतुलियाह के इस विशेष निष्कर्ष ने गंभीर जटिलताएं पैदा कीं और इसके परिणामस्वरूप कई वसूली की कार्यवाही को बढ़ावा मिला, साथ ही बकाया मांगों की वसूली में भी अड़चनें पैदा हुईं। इसलिए संसद ने कराधान कानून (वसूली कार्यवाही की निरंतरता और वैधता) अधिनियम, 1964 लागू किया, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। इस अधिनियम की खंड 3 में प्रावधान है कि अपील या अन्य कार्यवाहियों में किसी आदेश द्वारा सरकारी मांग को कम करने की स्थिति में कर प्राधिकरण के लिए निर्धारिती को मांग की एक नई सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, यह पर्याप्त होगा यदि कर प्राधिकरण ने निर्धारिती और कर वसूली अधिकारी को वसूली की राशि को कम करने के लिए सूचित किया और मांग की पिछली सूचना के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही वैध बनी रहेगी। इस हद तक सेघु बुकिया सेट्टी में इस अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया था।

गृह उद्योग बनाम बिक्री कर अधिकारी, सेक्टर 5, कानपुर, (1976) 37 एस. टी. सी. 483 वाले मामले में भी मांग नोटिस की सेवा का महत्व इस न्यायालय के विचार के लिए सामने आया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि मांग नोटिस की सेवा के बिना कोई वसूली नहीं हो सकती है; यदि ऐसा नोटिस नहीं दिया गया था, तो वसूली की कार्यवाही कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है और अमान्य है और वसूली प्रमाण पत्रों के साथ वही रद्द किए जाने योग्य हैं।

राम स्वरूप गुप्ता बनाम बिहारी लाल बलदेव प्रसाद और अन्य (1974) 95 आई. टी. आर. 339 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून पर कराधान कानून (सी. वी. आर. पी.) अधिनियम, 1964 के प्रभाव का उल्लेख किया। सेघु बुकिया सेट्टी का मामला और अभिनिर्धारित किया गया:-

“इन प्रावधानों का प्रभाव मांग की एक नई सूचना और वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करने और मूल वसूली कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देने के लिए है, लेकिन केवल अपील में कमी के बाद देय राशि के लिए, और इस उद्देश्य के लिए कर प्राधिकरण को निर्धारिती और कर वसूली अधिकारी को कटौती के तथ्य की सूचना भेजना आवश्यक है। चूँकि वसूली की कार्यवाही केवल उस राशि के लिए जारी रखी जा सकती है जो अंततः देय रहती है, और उससे अधिक किसी भी राशि के लिए नहीं, इसलिए कर वसूली अधिकारी को सूचना भेजने की आवश्यकता कर प्राधिकरण का एक आवश्यक कर्तव्य बन जाती है और इसे एक अनिवार्य शर्त माना जाना चाहिए। उस शर्त का पालन न करना प्रक्रिया में एक अवैधता होगी और कार्यवाही को अमान्य कर देगी। अपील में कमी के बाद, निर्धारिती द्वारा देय राशि से अधिक राशि की वसूली के लिए शुरू की गई और जारी रखी गई कार्यवाही में आयोजित बिक्री अमान्य होगी। इस तरह की बिक्री अधिनियम की खंड 3 के खंड (सी) द्वारा मान्य नहीं है।

राम स्वरूप गुप्ता के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले को भारत संघ बनाम जार्डिन हैंडरसन लिड, (1979) 118 [टीआर 112] में इस न्यायालय के समक्ष अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था, हालांकि इसे इस न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्यों पर लागू होने के लिए अलग किया गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने सुनील कुमार सिंह देव बनाम कर वसूली अधिकारी और अन्न मामले में निर्णय दिया है: (1987) 166 आई. टी. आर. 882 में कहा गया है कि मांग नोटिस की गैर-सेवा वसूली कार्यवाही शुरू करने वाले अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाती है। हम इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।

संयोग से, हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तीन खण्ड पीठ के फैसलों का उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात्, घनश्यामलाल बनाम एमपी राज्य, (1961) एम. पी. एल.] एस. एन. 218; मनमोहन लाल शुक्ला बनाम राजस्व बोर्ड, मध्य प्रदेश और अन्य, (1964) एम. पी. एल. जे. 32 और प्रेमचंद रामचंद बनाम राजस्व बोर्ड, एम. पी. और अन्य, (1964) एम. पी. एल. जे. 337 एम. पी. भूमि राजस्व संहिता, 1959 की खंड 146 में प्रावधान है कि भूमि राजस्व अवशिष्ट की वसूली के लिए कोई भी प्रक्रिया जारी करने से पहले तहसीलदार या नायब तहसीलदार किसी भी चूककर्ता को मांग की सूचना दे सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश पी. वी. दीक्षित ने तीनों मामलों में खंड पीठों की ओर से बोलते हुए कहा है कि 'मई' शब्द का अनिवार्य अर्थ 'होगा' है और मांग की सूचना दिए बिना वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, ऐसा न करने पर कार्यवाही क्षेत्राधिकार दोष से ग्रस्त होगी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय लंबे समय से इस दृष्टिकोण को गंभीरता से ले रहा है।

इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि दूसरी अनुसूची के तहत वसूली के लिए कदम उठाने से पहले अधिनियम की खंड 156 के तहत निर्धारिती पर मांग की सूचना की सेवा अनिवार्य है। मांग के नोटिस की गैर-सेवा वसूली के लिए बाद की कार्यवाही की वैधता की जड़ तक जाती है। मांग की सूचना दिए बिना शुरू की गई वसूली कार्यवाही में आयोजित बिक्री अमान्य होगी और इसलिए प्रश्न में बुलाए जाने पर रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगी।

सुरिंदर नाथ कपूर बनाम यूनियन ए. एफ. इंडिया एंड ओ. आर. एस., ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 1777 में, संपत्ति को कुर्क किया गया था और एक गार्निशी या डेट के अनुसार बेचा गया था, जो कि एक शून्य संलग्नक के कारण अस्तित्व में नहीं पाया गया था। बिक्री को अलग रखा गया था। इस न्यायालय ने कहा:

“गार्निषी आदेश जो पारित किया गया था वह अमान्य था और इस तरह के आदेश के अनुसार आयोजित कोई भी बिक्री भी अमान्य है। यह काफी मायने नहीं रखता कि बिक्री की पुष्टि की गई थी। जब कोई डिक्री या आदेश अवैध होता है, तो ऐसे डिक्री या आदेश के निष्पादन में आयोजित और पुष्टि की गई किसी भी बिक्री को इस आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है कि जब बिक्री किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में होती है तो यह अवैध थी। लेकिन, जब कोई डिक्री या आदेश अमान्य होता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाएगा और ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में आयोजित किसी भी बिक्री को भी अमान्य माना जाना चाहिए।”

वर्तमान मामले में, मांग नोटिस की गैर-सेवा के बारे में याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई गई है, हमारी राय में उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने से इनकार करके बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए था क्योंकि इसे उस तरीके से नहीं उठाया गया था जिस तरह से उच्च न्यायालय ने सोचा था कि इसे उठाया जाना चाहिए था। याचिका मामले की जड़ तक गई। यह याचिका आई. टी. ओ. से लेकर न्यायाधिकरण तक विभागीय अधिकारियों के समक्ष उठाई गई थी और उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं छोड़ी गई थी। उच्च न्यायालय के लिए आयकर विभाग को कार्यवाही का रिकॉर्ड पेश करने और यह दिखाने के लिए कहना मुश्किल नहीं होता कि क्या निर्धारिती को मांग का नोटिस दिया गया था। न्यायाधीश देने की प्रक्रिया में थोड़ा अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है जब यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति की मूल्यवान संपत्ति को ऐसे अवशिष्ट की वसूली के लिए बेचा जाना था जो बिल्कुल भी मौजूद नहीं था।

इस प्रकार, दोनों आधारों पर, हम मानते हैं कि प्रतिमुकदमी संख्या 3 के पक्ष

में मुकदमा संपत्ति की बिक्री को अलग रखा जा सकता है। अपील की अनुमति है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाएगी। विवादित संपत्ति की बिक्री के लिए सभी कार्यवाहियों के साथ-साथ बिक्री की पुष्टि करने वाले कर वसूली अधिकारी के आदेश को भी रद्द कर दिया जाता है।

बिक्री गिरने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जमा की गई खरीद राशि, जाहिर है, उसे वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी। उसे उस अवधि के लिए उपयुक्त ब्याज देकर क्षतिपूर्ति करने की भी आवश्यकता है जिसके लिए वह बिना किसी गलती के अपने पैसे के उपयोग से वंचित रही है। हमारी राय में, यह न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करेगा यदि रु। उसके द्वारा कर वसूली अधिकारी के पास जमा की गई आईडी 1 को वापस करने का निर्देश दिया जाता है और उसे प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिया जाता है। ब्याज के भुगतान का दायित्व किसे वहन करना चाहिए? जिस अवधि के लिए बिक्री को मांग के अस्तित्वहीन होने के कारण दूषित नहीं किया गया था, उसकी राय में, निर्धारिती को ब्याज का भुगतान करना चाहिए। एक बार जब मांग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और निर्धारिती द्वारा उस तथ्य को कर वसूली अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है, तो पूर्व को वसूली प्रमाण पत्र को रद्द कर देना चाहिए था और इसलिए, उस तारीख से धनवापसी की तारीख तक, ब्याज का भुगतान भारत संघ द्वारा किया जाना चाहिए, यानी, आयकर विभाग, जिसका प्रतिनिधित्व प्रतिवादी एन. ओ. एस. द्वारा किया जाता है। 1 और 2, जिसने भी पैसा रखा है और उसका उपयोग किया है। इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि रु. 1,70,000 इस निर्णय की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उत्तरदाता संख्या 1 और 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को वापस कर दिया जाएगा। 11.1.1980 से शुरू होने वाली अवधि के लिए रु 42,500, और 25.1.1980 से, रु 1,27,500, 22.11.1996 तक की गणना करते हुए,

अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा, जो भुगतान के चूक में, घर की संपत्ति से वसूल किया जा सकता है। आई. डी. 1 से धनवापसी की तारीख तक, प्रतिवादी संख्या 3 उत्तरदाता संख्या 1 और 2 से समान दर पर ब्याज वसूल करने का हकदार होगा। ब्याज की राशि की गणना भी आज से दो महीने की अवधि के भीतर की जाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि ब्याज विशुद्ध रूप से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत विचारों पर दिया जा रहा है, और ऐसा करने में हम एक मिसाल के रूप में पालन करने के लिए कानून के किसी भी सिद्धांत को निर्धारित नहीं कर रहे हैं। इन शर्तों में अपील की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

वीएसएस

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।